लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3213

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2024/22 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

यूरिया की मांग और उत्पादन

3213. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्री संजय दीना पाटिल:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्री अमर शरदराव काले:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में यूरिया की मांग और उत्पादन कितनी है और इसके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई नीतियों का संकेत देते हुए तथा इन नीतियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की क्या भूमिका परिकल्पित है;
- (ख) क्या सरकार नए यूरिया विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा घरेलू उत्पादन क्षमता के विस्तार के संदर्भ में अपेक्षित परिणाम क्या होंगे;
- (ग) क्या सरकार ने बंद पड़े यूरिया विनिर्माण संयंत्रों को पुनर्जीवित किया है या पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है;
- (घ) यदि हां, तो उनके स्थान तथा वर्तमान स्थिति सहित ब्यौरा क्या है;
- (ड.) क्या सरकार यूरिया उत्पादन में हरित हाइड्रोजन या अन्य टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को अपनाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा
- (च) सरकार द्वारा राज्यों में इनकी समान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ख): वर्ष 2023-24 के दौरान यूरिया की मांग 356.08 एलएमटी और यूरिया का उत्पादन 314.09 एलएमटी रहा। यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 और 7 अक्टूबर, 2014 को इसके संशोधन की घोषणा की थी। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुंडम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान

उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामतः गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमशः उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़पान-1।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा कार्यकुशल हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अतः, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान की 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) बढ़कर वर्तमान में 283.74 एलएमटीपीए हो गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने आरएसी के अतिरिक्त स्वदेशी यूरिया उत्पादन अधिकतम करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। इन उपायों से यूरिया उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 314.07 एलएमटी का रिकार्ड यूरिया उत्पादन हुआ है।

(ग) से (घ): सरकार ने फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआईएल) की रामागुंडम (तेलंगाना), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), सिंदरी (झारखंड) और तालचेर (ओडिशा) की इकाइयों और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बरौनी (बिहार) इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए नामित पीएसयू की संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के माध्यम से 12.7 एलएमटी प्रति वर्ष क्षमता के नए अमोनिया-यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए अधिदेशित किया है। रामागुंडम, गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी इकाइयों ने क्रमशः 22.03.2021, 07.12.2021, 18.10.2022 और 05.11.2022 को यूरिया उत्पादन शुरू किया है।

(ङ): राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च): सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

- i. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।
- ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को उर्वरकों की यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।
- iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;
- iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएण्डएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरक भेजने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
- v. उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) तथा उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मौसम में किए जाने वाले आयात को भी पहले से ही सुनिश्चित किया है।